ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 1, January 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.421

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 1, January 2023|

वर्तमान में भारत – अमेरिका संबंधों का बदलता स्वरूप: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Vinay Kumar Pinjani

Assistant Professor in Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

सार

हाल के समय में नई दिल्ली की ओर दौड़ लगाते दुनिया भर के राजनयिकों, अधिकारियों और मंत्रियों की लंबी सूची को देखें तो एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका का अनुमान लगाना पर्याप्त आसान हो जाता है।अमेरिका के संदर्भ में देखें तो भारत बाइडेन प्रशासन की 'इंडो-पैसिफिक' रणनीति का केंद्रबिंदु है और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ '2+2' बैठक में भाग लिया है।यद्यपि दोनों देश रूस-यूक्रेन संघर्ष—जो अभी वैश्विक भू-राजनीति के सबसे चिंताजनक मुद्दों में से एक है, पर एकसमान दृष्टिकोण नहीं रखते, किंतु मतभेदों से ऊपर उठना और निरंतर सहयोग सुनिश्चित करना दोनों देशों के पारस्परिक हित में है। भारत और अमेरिका के बीच हाल के दशकों में बढ़ती नज़दीकियों के बावजूद रूस-यूक्रेन संकट ने दोनों देशों के बीच कुछ मूलभूत मतभेदों को ज़ाहिर किया है.

अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार्रवाई के विरुद्ध, दबाव डालने के लिए साथ आ गए हैं. अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया जैसी एशियाई शक्तियां भी रूस के विरुद्ध प्रतिबंध लगा रही हैं.

हालांकि, भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिन्होंने यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की आक्रामकता की निंदा करने से ख़ुद को दूर रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फ़रवरी को पुतिन के साथ फ़ोन कॉल में सिर्फ़ 'हिंसा को तत्काल ख़त्म करने की अपील की.'

उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के यूक्रेन पर हमले के ख़िलाफ़ पेश किए गए प्रस्ताव पर भी भारत ने वोट नहीं किया.

परिचय

वर्तमान में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी कोविड-19 से मुकाबला, महामारी के बाद आर्थिक पुनरुद्धार, जलवायु संकट व सतत् विकास, महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियाँ, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, शिक्षा, प्रवासी समुदाय और रक्षा एवं सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों को अपने दायरे में लेती है। [1]भारत-अमेरिका संबंधों का विस्तार और गहनता अपूर्व है और इस साझेदारी के प्रेरक तत्व अभूतपूर्व वृद्धि कर रहे हैं।यह संबंध अभी तक अद्वितीय बना रहा है क्योंकि यह दोनों स्तरों पर संचालित होता है: रणनीतिक अभिजात वर्ग के स्तर पर भी और लोगों के आपसी संपर्क के स्तर पर भी।[2]यद्यपि रूस-यूक्रेन संकट के प्रति भारत और अमेरिका की प्रतिक्रियाएँ पर्याप्त विरोधाभासी रहीं, हाल की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह मत व्यक्त किया कि दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र पारस्परिक रूप से स्वीकार्य परिणामों पर पहुँचने के लिये अपने मतभेदों को दूर करने के इच्छुक हैं।भारत और अमेरिका ने हाल के वर्षों में संबंधों में आई गर्माहट पर आगे बढ़ते रहने और व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण को न खोने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है[3]। हालिया वर्षों में भारत ने अमेरिका को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज़ किया है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने न सिर्फ़ भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया बल्कि 'क्वाड' (एक समूह जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं) जैसे मंचों के माध्यम से बहुपक्षीय जुड़ाव को भी मज़बूत किया है.[4]

मुखर चीन के बारे में साझा चिंताओं ने इंडो-पैसिफ़िक में भारत और अमेरिका को एक-दूसरे के बेहद क़रीब ला दिया है. लेकिन रिश्तों की ये मधुरता दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में नहीं आ सकती है. जैसा कि रूस-यूक्रेन संकट में भारत और अमेरिका की अलग-अलग स्थिति से ज़ाहिर है. राष्ट्रपति जो बाइडन ने 24 फरवरी की टिप्पणी में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मंत्रणा हुई और वो रूस पर अपना रुख़ तय करने के मसले को "अभी हल नहीं कर पाए हैं."[5]

ये साफ़ दर्शाता है कि दोनों इस पर एक-दूसरे से अलग हैं. इससे पहले, व्हाइट हाउस ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो तनाव कम करने में भारत की भूमिका का स्वागत करता है और फिर उम्मीद जताई कि नई दिल्ली इस मुद्दे पर वॉशिंगटन का पक्ष लेगी.[6]

भारत के चीन के ख़िलाफ़ पश्चिम के समर्थन का फ़ायदा उठाने, लेकिन रूस की कार्रवाई पर ख़ामोश रहने के आरोप का जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में स्पष्ट तौर पर कहा कि इंडो-पैसिफ़िक और ट्रांस-अटलांटिक की स्थितियां 'एक समान' नहीं थीं. 19 फ़रवरी को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक पैनल चर्चा के दौरान, जयशंकर ने कहा कि "अगर दो परिस्थितियों के बीच संबंध होता तो यूरोपीय शक्तियां बहुत पहले इंडो-पैसिफ़िक में बहुत बेहतर हालत में होतीं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं देखा."

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 1, January 2023|

वर्तमान संकट पर भारत के अमेरिका का पक्ष न लेने पर विश्लेषक सुबीमल भट्टाचार्जी ने बीबीसी मॉनिटरिंग से कहा, "भारत के लिए इतिहास के सबक़ भूलना मुमकिन नहीं है. एक वक़्त था कि जब अमेरिका ने भारत के बदले पाकिस्तान का समर्थन किया था और ये रूस ही था कि जिसने भारत को अटूट समर्थन दिया. भारत के नीति निर्माता इसे नहीं भूलेंगे."[7]

विचार-विमर्श

इस वार्ता में 'स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये गए क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में सहयोग को गहरा करना चाहते हैं ताकि इन दोनों ही 'वॉर-फाइटिंग डोमेन' में क्षमताओं को विकसित किया जा सके।वे संयुक्त साइबर प्रशिक्षण एवं अभ्यास का विस्तार करते हुए एक आरंभिक 'रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वार्ता' (Defence Artificial Intelligence Dialogue) [30] आयोजित करने पर भी सहमत हुए।भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी भी तेज़ी से बढ़ रही है जहाँ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया है कि दोनों देशों ने "हिंद-प्रशांत के वृहत भूभाग में हमारी सेनाओं की परिचालन पहुँच का विस्तार करने और अधिक निकटता से समन्वय करने के लिये नए अवसरों की पहचान की है।"[8] अमेरिका ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख भी किया कि चीन भारत के साथ सीमा पर 'दोहरा उपयोग अवसंरचना' (dual-use infrastructure) का निर्माण कर रहा है और यह भारत के संप्रभु हितों की रक्षा के लिये उसके साथ खड़ा रहेगा।[9] मज़बूत भारत-रूस संबंध: [29]भारत-अमेरिका संबंध में रूस कोई नया कारक नहीं है। प्रतिबंधों के बीच भी भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी लाने के बजाय वृद्धि ही की है। रूस द्वारा भारत के लिये कम मूल्यों पर इसकी पेशकश की गई थी।भारत-रूस रक्षा संबंध भी भारत-अमेरिका संबंधों में एक अवरोध बना रहा है।भारत द्वारा रूस से 'S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली' की खरीद पर अमेरिकी CAATSA कानून के अनुपालन को लेकर भी लंबे समय से चर्चा जारी है।हालाँकि अमेरिका स्पष्ट रूप से यह भी समझता है कि भारत पर प्रतिबंध लगाने जैसा कोई भी कदम उनके संबंधों को फिर दशकों पीछे घसीट ले जाएगा।[10]अमेरिका की स्पष्ट चेतावनी (कि जो देश रूस पर प्रतिबंधों को दरकिनार करने या किसी प्रकार उसकी पूर्ति करने का सक्रिय प्रयास करेंगे, परिणाम भुगतेंगे) के बावजूद भारत और रूस डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणाली को दरकिनार कर द्विपक्षीय व्यापार कर सकने के तरीके तलाश रहे हैं। रूस-यूक्रेन संघर्ष भले ही भारत-अमेरिका के संबंधों की सीमाओं को उजागर कर दिया हो, लेकिन लंबे अरसे तक इसके प्रभाव पर राय जुदा हैं.[11]

कुछ भारतीय मीडिया ने इस बात पर रोशनी डाली है कि रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका की पाबंदियां भारत पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगी, जो रूस से अपने हथियारों का क़रीब 60 फ़ीसद आयात करता है.[28]

मशहूर हिंदी दैनिक नवभारत टाइम्स ने 24 फ़रवरी को अपने संपादकीय में कहा कि भारत के लिए रूस-यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव विशेष रूप से हथियारों की ख़रीद में नज़र आएगा. उस हिंदी दैनिक में कहा गया कि अमेरिका, भारत पर रूस से हथियार न ख़रीदने का दबाव बढ़ा सकता है. इसका असर भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली सौदे पर भी दिखाई देगा.[12]

रूस के ख़िलाफ़ अमेरिकी प्रतिबंध भारत और रूस के ज़रिए संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल के नियोजित निर्यात समेत कुछ और महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को प्रभावित कर सकते हैं; एक साथ 4 युद्धपोत बनाने का समझौता; भारत द्वारा Su-MKI और MiG-29 विमानों की ख़रीद; और बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए भारत-रूस की संयुक्त परियोजना भी प्रभावित हो सकती है.[13]

परिणाम

चीन के साथ सहयोग की भारत की संभावनाएँ: हाल के वर्षों में चीन ने अपनी अमेरिकी नीति के चश्मे से भूभाग में भारत के किसी भी कदम की समीक्षा की है, लेकिन यूक्रेन पर भारत के रुख के बाद बीजिंग में एक पुनर्विचार की शुरुआत हुई है।[14]हाल में चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा एक वृहत रणनीतिक 'रीसेट' की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जो भारत को 'क्वाड' से दूर करने की आवश्यकता से प्रेरित था।अपनी यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने दक्षिण एशिया में भारत की पारंपरिक भूमिका की रक्षा के साथ ही 'चीन-भारत प्लस' (China-India Plus) के रूप में विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने का दृष्टिकोण प्रकट किया [27]और इसके लिये एक वर्चुअल G-2 के निर्माण की पेशकश की।जबकि म्याँमार, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भारतीय और अमेरिकी नीतियाँ भिन्न हैं, चीन ऐसा विषय है जो दोनों देशों को एक साथ जोड़ता है।यदि अभी चीन के साथ भारत के संबंधों के पुनर्निर्माण का अवसर बनता है तो यह अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को बदल देगा और 'क्वाड' की प्रभावशीलता पर सवाल उठाएगा। हाल के घटनाक्रमों से भारत की हथियारों की ख़रीद को प्रभावित करने की संभावना के बावजूद, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.[15]

पूर्व भारतीय राजनयिक अमरेंद्र खटुआ ने बीबीसी मॉनिटरिंग को बताया कि हथियारों के आयात में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन भारत और अमेरिका एक-दूसरे से दूर जाने के जोखिम नहीं उठा सकते, ख़ासकर तब जब चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है.[16]

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 1, January 2023|

अमरेंद्र खटुआ अर्जेंटीना और आइवरी कोस्ट में भारत के राजदूत रह चुके हैं. उन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी संघ के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. कुछ लोगों ने भारत को अपने रुख़ में बदलाव की सलाह दी.[26]
भारत सरकार का सीमित सार्वजनिक संचार और मौजूदा संकट के लिए पुतिन की निंदा करने से इनकार करना, पूरी तरह से असामान्य नहीं है, ख़ास तौर पर देश की विदेश नीति के रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत की पृष्ठभूमि के ख़िलाफ़ ऐसा करना.[17]
नई दिल्ली ने पक्ष ना लेने के बारे में अपने रुख़ को दृढ़ता से रखा है. हालांकि कुछ विशेषज्ञों और मीडिया ने टिप्पणी की है कि भारत सरकार के लिए परिस्थितियां इतनी आसान नहीं हो सकती हैं[25].

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग: राजनीतिक मामलों की अमेरिकी विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान स्वीकार किया कि "रक्षा आपूर्ति के लिये रूस पर भारत की निर्भरता महत्त्वपूर्ण है" और यह "उस युग में सोवियत संघ और रूस से सुरक्षा समर्थन की विरासत है जब अमेरिका भारत के प्रति कम उदार रहा था।"हालाँकि, आज की नई वास्तविकताओं के साथ इस द्विपक्षीय संलग्नता के प्रक्षेपवक्र के आकार लेने के साथ यह उपयुक्त समय होगा जब अमेरिका भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ सह-उत्पादन और सह-विकास के माध्यम से अपना रक्षा विनिर्माण आधार बनाने में मदद करे।[18]

अवसरों की खोज: भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में—जो एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। यह अपनी वर्तमान स्थिति का उपयोग अपने महत्त्वपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिये कर सकता है।भारत और अमेरिका आज इस संदर्भ में सही अर्थों में रणनीतिक साझेदार हैं कि यह परिपक्व प्रमुख शक्तियों के बीच ऐसी साझेदारी है जो पूर्ण अभिसरण की तलाश नहीं कर रही है, बल्कि निरंतर संवाद [24]सुनिश्चित कर और असहमतियों को नए अवसरों को गढ़ने में निवेश कर मतभेदों का प्रबंधन कर रही है।सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग: यूक्रेन संकट के परिणामस्वरूप चीन के साथ रूस का बढ़ा हुआ संरेखण चीन से मुकाबले के लिये केवल रूस पर भरोसा कर सकने की भारत की क्षमता को जटिल बनाता है। इसलिये अन्य सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग जारी रखना दोनों देशों के हित में है।चीनी सेना की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को लेकर व्याप्त चिंताएँ अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों में अंतरिक्ष शासन को भी एक प्रमुख विषय बनाती है। खटुआ ने कहा कि भारत सरकार असल में एक चौराहे पर है. वह चाहती है कि अमेरिका चीन से निपटे, लेकिन वह सभी हथियारों के लिए रूस का साथ भी चाहता है. इसलिए बीच में फंसना कोई अच्छी स्थिति नहीं है.[19]
अंग्रेज़ी दैनिक 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने एक रिपोर्ट में कहा है, "अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक से दबाव के साथ, ये नई दिल्ली के लिए रणनीतिक विकल्प बनाने के लिए एक परीक्षा है. एक तरफ़ सिद्धांत और मूल्य हैं तो दूसरी तरफ़ व्यावहारिकता और हित हैं.[23]
जबकि प्रमुख भारतीय मीडिया आउटलेट्स को रूस के कार्यों की आलोचना करने से काफ़ी हद तक दूर रखा गया है, मीडिया के एक वर्ग ने इस मुद्दे पर भारत की स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है.[20]
मशहूर पत्रकार प्रणब ढल सामंता ने अंग्रेज़ी के प्रमुख बिज़नेस अख़बार 'द इकोनॉमिक टाइम्स' में एक टिप्पणी में लिखा कि भारत को "रूस के साथ अपने संबंधों पर एक कठोर, और दीर्घकालिक नज़र" विशेष रूप से भारत के प्रतिद्वंदियों चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रूस से रिश्तों की पृष्ठभूमि पर नज़र डालने की ज़रूरत है.[22]
इसी तरह, अंग्रेज़ी के सबसे ज़्यादा प्रसारित दैनिक 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में एक संपादकीय ने आगाह किया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के साथ संबंध "पहले से कहीं ज़्यादा अहम हैं" और इसे बनाए रखने के लिए "अपने वर्तमान राजनयिक रुख़ के पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत होगी, जो कि एक मुख्य सवाल है."[21]

संदर्भ

1. कोहेन, स्टीफन पी। (जनवरी 2010)। महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष - पाकिस्तान और शीत युद्ध (पीडीएफ) । ब्रूकिंग्स। पीपी. 76, 77, 78. आईएसबीएन 978-0-415-55025-3.
2. ^ "भारत के दूतावास, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में आपका स्वागत है" । 26 मार्च, 2016 को मूल से संग्रहीत । 2 अप्रैल, 2016 को पुनःप्राप्त ।
3. ^ "भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के सिद्धांत" (पीडीएफ) । dpcc.co.in। _ 4 मई, 2012 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 25 मार्च, 2018 को पुनःप्राप्त ।
4. ↑ "मोदी सरकार का एक साल: हम बनाम देम" । इंडियन एक्सप्रेस । मई 25, 2015।
5. ^ "ओबामा-मोदी वार्ता के बाद भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य" । द हिंदू । जनवरी 25, 2015।

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 1, January 2023|

6. ↑ "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक भारत-अमेरिका विवाद" । राजनयिक । जून 11, 2015।
7. ^ "भारत, यूएस साइन लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट" । राजनयिक । 30 अगस्त 2016 को पुनःप्राप्त ।
8. ^ "मजबूत रक्षा संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, अमेरिका, भारत ने सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए" । द जापान टाइम्स । अगस्त 30, 2016 । 30 अगस्त 2016 को पुनःप्राप्त ।
9. ↑ "भारत, अमेरिका ने प्रमुख रक्षा भागीदार समझौते को अंतिम रूप दिया" । द इंडियन एक्सप्रेस । दिसम्बर 9, 2016 । 9 दिसंबर, 2016 को पुनःप्राप्त ।
10. ^ कुगेलमैन, माइकल (14 जुलाई, 2022)। "एक और क्राउड राइज़" । विदेश नीति।
11. ^ "कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन अमेरिकियों के सबसे पसंदीदा राष्ट्र हैं" । गैलप डॉट कॉम। मार्च 13, 2015।
12. ^ "उत्तर कोरिया अमेरिकियों के बीच सबसे कम लोकप्रिय देश बना हुआ है" । गैलप डॉट कॉम। फरवरी 20, 2017 । 6 फरवरी, 2018 को पुनःप्राप्त ।
13. ^ "अमेरिकियों के चीन के अनुकूल विचार 12-पॉइंट हिट लेते हैं" । गैलप डॉट कॉम । 11 मार्च, 2019 । 8 सितंबर, 2019 को पुनःप्राप्त ।
14. ^ इंक, गैलप (3 मार्च, 2020)। "ईरान, उत्तर कोरिया को अमेरिकियों ने सबसे कम पसंद किया" । गैलप डॉट कॉम । 21 फरवरी, 2021 को पुनःप्राप्त । {{cite web}}: |last1=सामान्य नाम है (मदद)
15. ^ इंक, गैलप (14 मार्च, 2022)। "अमेरिकियों ने कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान को सर्वाधिक अनुकूल दर दिया" । गैलप डॉट कॉम । 20 अप्रैल, 2022 को पुनःप्राप्त । {{cite web}}: |last=सामान्य नाम है (मदद)
16. ↑ "हाउ द वर्ल्ड सीज़ अमेरिका एमिड इट्स चाओटिक विदड्रॉल फ्रॉम अफ़ग़ानिस्तान" । 26 अगस्त, 2021।
17. ^यहां तक जायें:a b "अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना, चीन को पछाड़ा"। एनडीटीवी। 29 मई, 2022को पुनःप्राप्त।
18. ^ ग्रांट, आरजी (24 अक्टूबर, 2017)। 1001 लड़ाइयाँ जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया । पुस्तक बिक्री, 2017. आईएसबीएन 978-0785835530.
19. ^ बोसवेल, जेम्स (1783)। ईस्ट इंडीज ऐप 1783 में मामले - वाइस-एडम से एक पत्र का उद्धरण। श्री स्टीफंस को सर एडवर्ड ह्यूजेस । स्कॉट्स पत्रिका । पीपी। 685-688।
20. ^ फॉसेट, सर चार्ल्स (1937)। "ईस्ट इंडिया कंपनी का धारीदार झंडा, और अमेरिकी 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' के साथ इसका संबंध " द मेरिनर मिरर । 23 (4): 449–476। डोई : 10.1080/00253359.1937.10657258 ।(सदस्यता आवश्यक)
21. ^ यूजीन वैन सिकल। "1812 के युद्ध में कांग्रेव रॉकेट्स" (पीडीएफ) । डाल्टन स्टेट कॉलेज । 25 दिसंबर 2014 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 9 दिसंबर 2014 को पुनःप्राप्त ।
22. ^ होल्डन फर्बर, "हिस्टॉरिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो-अमेरिकन रिलेशंस," जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे (1965), वॉल्यूम। 34 अंक 67/68, पीपी 95-116।
23. ^ श्मिट, बारबरा। "ज्ञात मार्क ट्वेन के भाषणों, सार्वजनिक रीडिंग और व्याख्यानों का कालक्रम" । Marktwainquotes.com । 1 जनवरी, 2013 को पुनःप्राप्त ।
24. ^ गुप्ता, विपिन; सरन, पंकज (2007). लेनिनसन, डेविड; क्रिस्टेंसेन, करेन (सं।)। संयुक्त राज्य अमेरिका पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य: राष्ट्र सर्वेक्षण द्वारा एक राष्ट्र । वॉल्यूम। 1. ग्रेट बैरिंगटन, एमए: बर्कशायर पब्लिशिंग ग्रुप। पीपी। 294–300 । आईएसबीएन 978-1-933782-06-5.
25. ↑ इसहाक, हमारे दिमाग पर खरोंच: चीन और भारत के अमेरिकी दृश्य (1980) पृष्ठ 241
26. ↑ फोस्टर रिया डलेस, और जेराल्ड ई. राइडिंगर। "फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट की उपनिवेश विरोधी नीतियां।" राजनीति विज्ञान त्रैमासिक (1955): 1-18। जेएसटीओआर में
27. ^ केंटन जे। क्लाइमर, क्वेस्ट फॉर फ्रीडम: द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस (2013)।
28. ^ गोंजालेस, जुआन एल जूनियर (1986)। "एशियाई भारतीय आप्रवासन पैटर्न: कैलिफोर्निया में सिख समुदाय की उत्पत्ति"। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा । 20 (1): 40-54। डीओआई : 10.1177/019791838602000103 । जेएसटीओआर 2545683 । एस2सीआईडी 145124856 .
29. ^ रुबिन, एरिक एस। (2011)। "अमेरिका, ब्रिटेन और स्वराज: एंग्लो-अमेरिकन रिलेशंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस, 1939-1945"। इंडिया रिव्यू । 10 (1): 40-80। डीओआई : 10.1080/14736489.2011.548245 । एस2सीआईडी 154301992 .
30. ^ हरमन, आर्थर (2008)। गांधी और चर्चिल: महाकाव्य प्रतिद्वंद्विता जिसने एक साम्राज्य को नष्ट कर दिया और हमारे युग को जाली बना दिया । रैंडम हाउस डिजिटल, इंक। पीपी। 472-539। आईएसबीएन 978-0-553-80463-8.

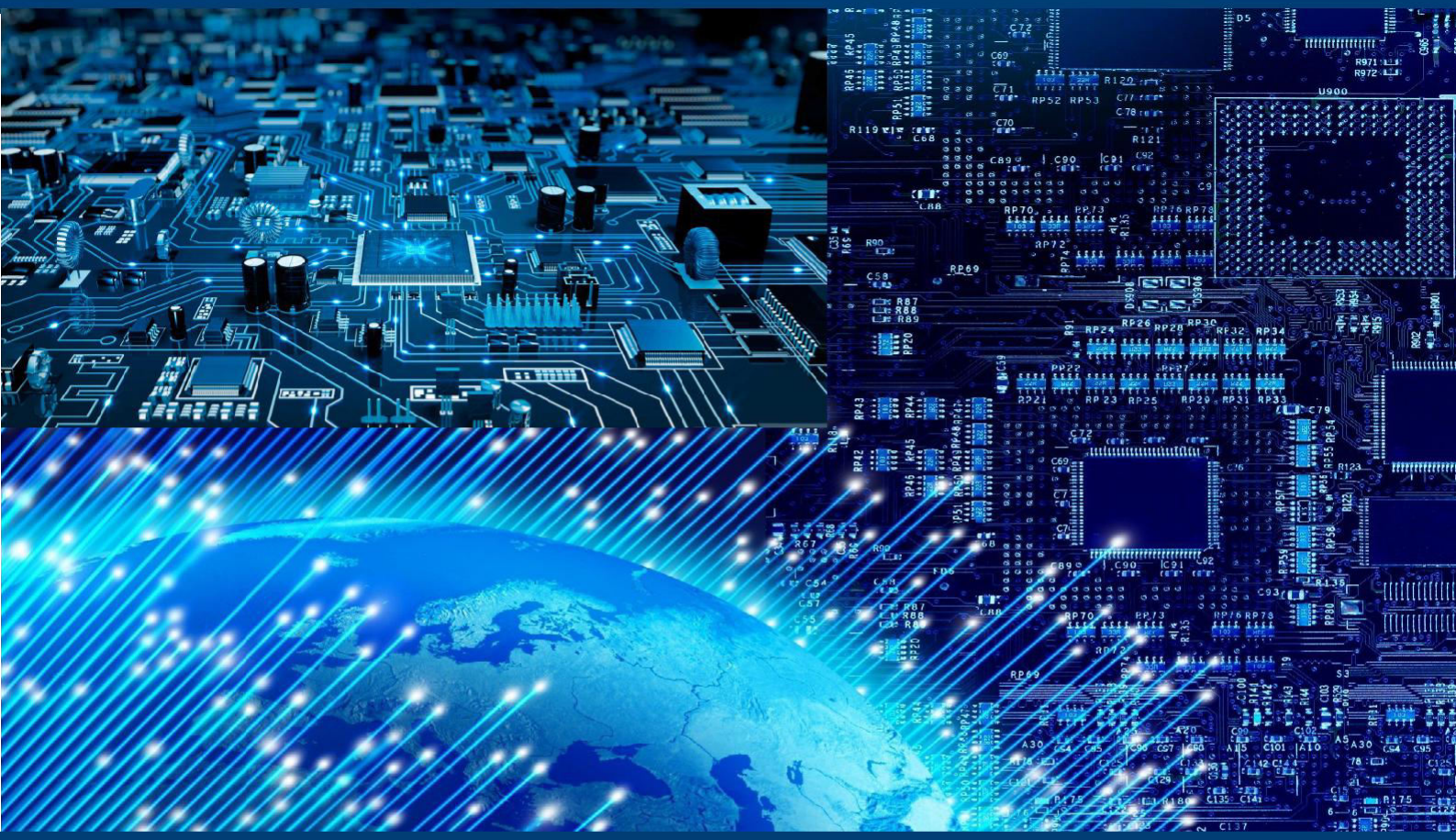

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |